

TEACHERS अगर काबिल न हों तो !

जर्जर स्कूल, कमजोर व्यवस्था और नेतृत्वविहीन शिक्षा पर तीखा कटाक्ष

जिस देश के स्कूलों की छत टपकती हो, शिक्षक पर्याप्त न हों, शिक्षा नेतृत्व दिशाहीन हो और व्यवस्था जवाबदेही से भागती हो—वह देश अपने भविष्य से क्या उम्मीद कर सकता है?

आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि "Teacher काबिल है या नहीं?" असली सवाल यह है कि पूरी Education System कितनी काबिल है?

एक तरफ हम विश्वगुरु बनने के सपने देखते हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, स्मार्ट क्लास और नई शिक्षा नीति के बड़े-बड़े दावे करते हैं; दूसरी तरफ देश के अनेक हिस्सों में बच्चे जर्जर कमरों, टूटी दीवारों, खराब शौचालयों, पीने के पानी की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं।

वाह रे व्यवस्था! भाषणों में आधुनिक शिक्षा, जमीन पर जर्जर विद्यालय!

कहीं शिक्षक नहीं, कहीं विषय विशेषज्ञ नहीं, कहीं एक ही शिक्षक पर कई कक्षाओं का बोझ। कहीं शिक्षक हैं तो संसाधन नहीं, संसाधन हैं तो नेतृत्व नहीं और नेतृत्व है तो दृष्टि, ईमानदारी और जवाबदेही का अभाव!

शिक्षा व्यवस्था को केवल किताब, बोर्ड और परीक्षा समझ लेने की भूल कब तक चलेगी?

जर्मनी का राष्ट्र निर्माता है—लेकिन जर्मनी को राष्ट्र निर्माण का वातावरण कौन देगा?

अगर योग्य शिक्षक की भर्ती समय पर नहीं होगी, प्रशिक्षण केवल कागजी खानापूति बनेगा, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों में उलझाया जाएगा, तबादले और नियुक्तियां पारदर्शी नहीं होंगी और अच्छे काम का सम्मान तथा खराब काम की जवाबदेही तय नहीं होगी—तो परिणाम कैसे बदलेंगे?

और Education Leadership?

यही तो सबसे बड़ा सवाल है।

जिस व्यवस्था का नेतृत्व ही दूरदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह नहीं होगा, वहां नीचे बैठे लोगों से चमत्कार की उम्मीद करना भी व्यवस्था की विडंबना है।

नीति ऊपर बनती है, बोझ नीचे उतरता है और जवाबदेही अंततः शिक्षक पर डाल दी जाती है।

कभी पाठ्यक्रम बदलता है, कभी परीक्षा प्रणाली, कभी योजना, कभी ऐप, कभी रिपोर्ट—लेकिन क्या बच्चे की वास्तविक सीखने की क्षमता भी उतनी ही तेजी से बदल रही है?

शिक्षा को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने से पहले यह पूछना होगा कि सरकारी स्कूल का बच्चा निजी स्कूल के बच्चे के बराबर अवसर कब पाएगा?

यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं है। यह समानता, अवसर, गरिमा और मानवाधिकार का प्रश्न है।

AIHRA मानता है कि किसी बच्चे का भविष्य उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, उसके गांव, उसके स्कूल की जर्जर दीवार या व्यवस्था की लापरवाही से तय नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां योग्यता को सम्मान, शिक्षक को संसाधन, विद्यार्थी को अवसर और व्यवस्था को जवाबदेही मिले। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम समस्या को जानते हैं, फिर भी वर्षों तक उसे ढोते रहते हैं।

जर्जर भवन दिखाई देता है—फिर भी मरम्मत फाइलों में अटकती है।

शिक्षकों की कमी दिखाई देती है—फिर भी पद खाली रहते हैं।

बच्चों की कमजोरी दिखाई देती है—फिर भी आंकड़ों की चमक दिखाई जाती है।

नेतृत्व की कमी दिखाई देती है—फिर भी कुर्सियां भरी रहती हैं।

यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे कड़वा सच!

अब समय आ गया है कि स्कूल की दीवार से लेकर मंत्रालय की मेज तक पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय हो।

हमें केवल अच्छे Teacher नहीं चाहिए—हमें अच्छी व्यवस्था, मजबूत नेतृत्व, पर्याप्त बजट, सुरक्षित भवन, आधुनिक संसाधन, पारदर्शी भर्ती, निरंतर प्रशिक्षण और कठोर जवाबदेही चाहिए।

क्योंकि—

“जर्जर भवन में मजबूत भविष्य नहीं बनता, कमजोर नेतृत्व में मजबूत शिक्षा नहीं बनती, और कागजी योजनाओं से राष्ट्र का भविष्य नहीं बनता।” शिक्षा को भाषणों से नहीं, ईमानदार व्यवस्था से बचाना होगा।

आज फैसला करना होगा — क्या हम केवल स्कूल खोलना चाहते हैं या भविष्य बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर जवाब भविष्य बनाना है, तो फिर — Teachers अगर काबिल न हों तो सुधारो, Buildings जर्जर हों तो बनाओ, System खराब हो तो बदलो, Leadership कमजोर हो तो जवाबदेह बनाओ — लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ समझौता मत करो!”

AIHRA की आवाज स्पष्ट है—शिक्षा कोई सरकारी योजना भर नहीं, राष्ट्र की आत्मा और हर बच्चे का अधिकार है।

“IF TEACHERS ARE NOT CAPABLE—THEN WHAT ABOUT THE ENTIRE SYSTEM?”

A Hard-Hitting Special Article on the Collapse of Education Infrastructure,

Leadership and Accountability

If the roofs of schools are leaking, buildings are crumbling, teachers are insufficient, educational leadership is directionless and the system keeps escaping accountability—what future can we honestly expect for the nation?

The question is not merely whether a teacher is capable or incapable. The bigger question is: How capable is the entire education system?

On one side, we talk about becoming a Vishwaguru, celebrate Digital India, smart classrooms and ambitious education policies. On the other, in many places, children are still studying in dilapidated classrooms, unsafe buildings, broken facilities, inadequate toilets and without basic drinking water.

What a contradiction! Modern education in speeches, but broken schools on the ground!

Some schools have no adequate teachers. Some lack subject specialists. In some places, one teacher carries the burden of

several classes. And where teachers are available, there may be a shortage of resources, effective administration, vision and—most importantly—accountability.

Can education really be reduced to textbooks, examinations, attendance figures and certificates?

A teacher is a nation-builder—but who will build the environment in which that nation-builder can actually perform?

If qualified teachers are not recruited on time, if training becomes a mere formality, if teachers are burdened with endless non-academic duties, if transfers and appointments lack transparency, and if neither excellence is rewarded nor negligence is properly addressed—then how can we expect educational outcomes to improve?

And then comes the biggest question:

WHERE IS EDUCATIONAL LEADERSHIP?

A system without visionary, sensitive and accountable leadership cannot produce extraordinary results merely by issuing circulars and changing policies.

Policies are designed at the top, burdens are pushed downward, and accountability is often ultimately placed on the teacher.

New curriculum. New examination pattern. New scheme. New app. New report.

But the fundamental question remains:

Is the child actually learning?

Before turning education into a political laboratory, we must ask whether a child studying in a government school receives the same quality of opportunity as a child from a privileged background.

This is not merely an education issue.

It is an issue of equality, opportunity, dignity and human rights.

AIHRA firmly believes that the future of a child must not be determined by poverty, geography, a village school, a leaking roof or administrative negligence.

Every child deserves a system where merit is respected, teachers are supported, students receive opportunities and institutions are held accountable.

The most dangerous part is that we often know the problems—and still allow them to continue for years.

The broken school building is visible—yet repair remains trapped in files.

Teacher vacancies are visible—yet posts remain vacant.

Learning gaps are visible—yet impressive statistics are displayed.

Leadership failures are visible—yet the chairs remain occupied.

This is the bitter irony of our education system.

The time has come to demand accountability from the classroom to the ministry, from the school building to the highest level of educational leadership.

We do not need only better teachers.

We need better infrastructure, stronger leadership, adequate funding, safe school buildings, modern resources, transparent recruitment, continuous teacher training and genuine accountability.

Because—

“A broken building cannot build a strong future. Weak leadership cannot build strong education.

And paperwork cannot build a strong nation.” Education cannot be rescued by speeches, slogans and publicity campaigns. It requires honest governance, competent leadership and measurable accountability.

So the nation must decide: Are we merely opening schools—or are we actually building the future? If the answer is building the future, then— Improve the teacher if the teacher needs improvement. Rebuild the school if the building is unsafe. Reform the system if the system is failing. Strengthen leadership if leadership is weak. But never compromise with the future of our children.

AIHRA's message is clear:

Education is not merely a government programme. It is the foundation of the nation—and every child's fundamental claim to dignity, opportunity and a better future.

